बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित होने वाली अंतर-संसदीय संघ (IPU) की 141 वीं बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के उपयोगार्थ 'सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति विवेकपूर्ण उपभोग और उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु सर्कुलर अर्थव्यवस्था और डिजीटलीकरण का व्यापक प्रयोग '

13-17 अक्टूबर 2019

हम सभी जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संख्या 12, जो विवेकपूर्ण उपभोग और उत्पादन सुनिश्चित करने से संबंधित है, को प्राप्त करने के लिए गैर-नवीकरणीय संसाधनों और इसकी पुनर्योजी क्षमता पर अनावश्यक दवाब बनाए बिना अपने सीमित प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक उपयोग करना आवश्यक है।

मित्रो, सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विकास और हित के लिए डिजिटलीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था के अनुरूप डिजिटलीकरण में सामाजिक-राजनीतिक-प्रशासनिक क्षेत्र में दक्षता लाने की क्षमता है। डिजिटलीकरण के इस युग में, पेपरलेस प्रणाली न केवल पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त होगी, बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच के अन्तराल का पता लगाने में भी सहायक हो सकती है, जिससे प्रभावी नीतियां तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी । सर्कुलर अर्थव्यवस्था की दिशा में उठाए गए कदम संसाधन दक्षता के महत्वपूर्ण अंग हैं और ये अधिक स्थायी आर्थिक विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होंगे । डिजिटलीकरण को मुख्यधारा में लाने और लिनियर अर्थव्यवस्था से एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर जाने से हमें सतत विकास लक्ष्य 12 को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

गण्यमान्य प्रतिनिधिगण, भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, समावेशी और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। एक ओर, हमने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं दूसरी ओर, हमने सभी के लिए सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का व्यापक विस्तार, सभी के लिए स्वच्छता और आवास, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, आदि पर कार्यवाही करते हुए सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है ।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए लोगों के जीवन को बदलने के लिए टिकाऊ डिजिटल तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। सरकार देशवासियों को कम से कम समय में सुशासन और किफायती सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटलीकरण और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलें स्वच्छ, हरित और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

गण्यमान्य प्रतिनिधिगण, भारत की संसद ने सतत विकास लक्ष्य एजेंडे के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। लोक सभा ने वर्ष 2015 और 2016 में सतत विकास लक्ष्य पर

व्यापक चर्चा की, जिसमें मेरे सहयोगियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। वर्ष 2017 में भारत में इंदौर में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के बारे में दक्षिण एशियाई देशों की संसद के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने की अनिवार्यता को दोहराया गया। 'सतत विकास लक्ष्यों के लिए संसाधनों और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने' संबंधी शिखर सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के उद्देश्य से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सांसदों से सभी पक्षकारों के सहयोग से सामूहिक रूप से कार्यवाही करने का आग्रह किया गया। संसदीय स्थायी समितियों ने डिजिटलीकरण और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न सिफारिशें देकर सजग और सक्रिय होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

देवियों और सज्जनो, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण की प्रक्रिया और अन्य नवोन्मेषी उपायों का लगातार अनुसरण करेगा और इस प्रकार विवेकपूर्ण उत्पादन और उपभोग के माध्यम से संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेगा। मुझे आशा है कि इस विचार-विमर्श का परिणाम लाभप्रद होगा।